Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 7, December-2021, ISSN 2230-7540

18वीं शताब्दी राजस्थान में एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के उद्भव की खोज

सुख लाल यादव[1*], डॉ. राजीव कुमार जैन[2]

[1] पीएच.डी शोधकर्ता, सनराईस विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

[2] प्रोफेसर (कला विभाग), सनराईस विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार - *18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के दौरान राजस्थान में मुगल साम्राज्य के पतन ने इसकी राजनीति , समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण की शुरुआत की। क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्भव और व्यावसायीकरण की एक नई धारणा ने व्यापारियों और व्यापारियों के जुड़ाव के क्षेत्र को चौड़ा कर दिया और इसके राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी परिणाम थे। यह पत्र मुगल व्यवस्था के राजनीतिक विघटन और स्थानीय रियासतों के उदय से होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रक्षेपवक्र का पता लगाता है। विशेष रूप से यह देखता है i) कृषि में गैर-किसान क्षेत्र का उदय, ii) राज्य में एक क्रॉस-जाति व्यापारी वर्ग का उदय और iii) रियासतों, व्यापारियों, कारीगरों और के बीच नए शासन के तहत वाणिज्यिक संबंधों में बदलाव व्यापारी। यह शोध बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार से समृद्ध अभिलेखीय प्राथमिक स्रोतों की अंतर्दृष्टि पर आधारित है, मुख्य रूप से बाहियों की सावधानीपूर्वक और व्यापक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गांव की संरचना में परिवर्तन का पता लगाने के लिए , जो क्षेत्रीय जेंट्री ने राजनीतिक का मुकाबला करने की कोशिश की थी। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस अध्ययन में फलते-फूलते व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते व्यावसायीकरण और मुद्रीकरण के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक समृद्धि आई , इस प्रकार यह तथ्य स्थापित हुआ कि 18वीं शताब्दी में आर्थिक और सामाजिक पतन की प्रक्रिया को 'एक' के रूप में भी जाना जाता है। अंधकार युग' मौजूदा साहित्य में, सार्वभौमिक नहीं था।*

शब्द कुंजी - *कारीगर, व्यापारी, राजस्व, राज्य, शहर, व्यापार संवर्धन।*

----------X----------

परिचय

अठारहवीं शताब्दी को देश में संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है , क्योंकि भारत ने अपनी शक्ति संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे , जिसने महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पुनर्गठन की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ कई राज्यों ने एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था का उदय देखा। इतिहासकार , जो इस सदी को अकेले मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में जांचते हैं , मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक पतन की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं , जिसके परिणामस्वरूप मुगल व्यवस्था का राजनीतिक विघटन हुआ , और युग को 'अंधकार युग' के रूप में लेबल करते हैं। हालाँकि , अब व्यापक साहित्य मौजूद है जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक गिरावट सार्वभौमिक नहीं थी और देश के कई हिस्सों में आर्थिक समृद्धि के अलग-अलग क्षेत्र थे। राजस्थान ने विशेष रूप से अपनी सामाजिक-राजनीतिक अर्थव्यवस्था में दिलचस्प संरचनात्मक परिवर्तन देखे , जिसने राज्य के अधिकांश हिस्सों में राजनीतिक और आर्थिक उछाल को प्रोत्साहित किया। इन परिवर्तनों में नए क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों का उदय शामिल था , जो जेंट्रीफिकेशन प्रक्रिया द्वारा सह-गठित थे (i)

महत्वपूर्ण राजनीतिक रसूख के साथ एक जीवंत क्रॉस-कास्ट व्यापारी वर्ग का उदय , (ii) व्यापारियों, व्यापारियों और किसानों का सह-संयोजन राजस्व खेती की प्रणाली फली-फूली और नए कस्बों और बाजारों का उदय हुआ , और (iii) बढ़ता व्यावसायीकरण और मुद्रीकरण जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था ने अपने वित्तीय संस्थागत ढांचे को मजबूत किया।

18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, राजस्थान में स्थानीय शासक वर्ग , राजपूत रियासतों ने अपनी जागीरों को मजबूत करना शुरू कर दिया , ताकि घटती मुगल वित्तीय स्थिति की स्थिति में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उत्तोलन बनाए रखा जा सके। और सैन्य समर्थन , मराठों और पिंडारियों द्वारा बार-बार प्रस्ताव के साथ संयुक्त , जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महाराजा जय सिंह सवाई (1688-1743) के रूप में काफी समेकन देखा गया, जिन्होंने धीरे-धीरे राजस्थान के अधिकांश परगनाओं पर कब्जा कर लिया, जो 'कोर' मुगल क्षेत्रों (रायचौधरी और अन्य , 1883) का हिस्सा थे।

चूंकि जागीरदार अक्सर नई जागीरों में चले जाते थे , स्थानीय प्रशासन और राजस्व संग्रह के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया था जो ऐसे कार्यों में कुशल थे। इन स्थानीय राजस्व अधिकारियों जैसे कि पटेलों और पटवारियों ने नए जेंट्री समूह का गठन किया , जो रियासतों और कृषि अर्थव्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा करते हुए काफी शक्ति और महत्व के पदों तक पहुंचे। स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों जैसे किसानों , कारीगरों, व्यापारियों और व्यापारियों के साथ राजस्व अधिकारियों के जुड़ाव और गठजोड़ रियासतों के आसन्न संचित ऋण द्वारा बनाई गई वित्तीय गड़बड़ी को दूर करने के तरीके खोजने के लिए आसन्न थे। धन के स्रोतों को खोजने के लिए , राज्य (जिसमें रियासतें और उनके स्थानीय अधिकारी शामिल थे) कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार पर निर्भर थे। व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से वित्तीय संसाधनों के व्यवस्थित संगठन ने कृषि उत्पादन का विस्तार करने में मदद की , जबकि नए व्यापार मार्गों के खुलने से व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि हुई क्योंकि नए बाजार और कस्बों का उदय हुआ। जैसे-जैसे व्यापार और वाणिज्य फलता-फूलता गया, राज्य ने विभिन्न करों, शुल्कों और उपकरों के माध्यम से इन गतिविधियों से भारी मात्रा में राजस्व अर्जित किया। व्यापार के फलने-फूलने और इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने के कारण राजस्थान की अधिकांश रियासतें फली-फूलीं।

इस प्रकार से बाकी के पेपर आयोजन गया है। पेपर का खंड 2 इस अध्ययन के लिए संदर्भित व्यापक अभिलेखीय डेटा पर विस्तार से बताता है। इस पत्र के माध्यम से , जहाँ भी प्राथमिक स्रोत का उल्लेख करने की आवश्यकता है , विवरण फुटनोट में प्रदान किया गया है। खंड 3 में राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा और 18वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित ग्राम संरचना प्रस्तुत की गई है। कृषि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जिसके कारण राज्य में एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, खंड 4 में रेखांकित किया गया है। खंड 5 नए शहरों और बाजारों के आने के साथ व्यापार नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा करता है। निष्कर्षों को खंड 6 में संक्षेपित किया गया है।

राज्य अभिलेखीय डेटा

यह शोध बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार में रखे गए विभिन्न अभिलेखीय आंकड़ों की अंतर्दृष्टि पर आधारित है। दस्तावेज़ आमेर प्रशासन के लिए विपुल डेटा प्रदान करते हैं। कुछ अभिलेखों में कुछ जागीरों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा तब होता था जब कुछ जागीरें या परगने एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में जाते थे। जहां तक संभव हो , यह पत्र परगना (जैसे अंबर या जयपुर, बसवा, दौसा आदि) के निरंतर अभिलेखों पर निर्भर करता है जो ज्यादातर आमेर शासकों के अधिकार में रहे। मारवाड़ क्षेत्र का मुख्य संदर्भ नैन्सी का विगत4 है।

राजस्थान की रियासतों ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की , जिसमें कई अधिकारी और अन्य अधिकारी दैनिक लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने के प्रभारी थे। इस तरह के विवरण दर्ज करने वाले दस्तावेजों को दो रूपों में रखा गया था अर्थात बाहिस (लंबे दस्तावेज़ जो मुड़े हुए हैं) और टोज़िस (ढीले कागज़)। इनमें से कुछ दस्तावेज़ों में शामिल हैं: जमाबंदी (पैसे के लेन-देन दर्ज करने वाले दस्तावेज़) ; सनद परवाना बहिस (क्षेत्रों और प्रांतों में व्यापार के रिकॉर्ड , व्यापार मार्ग, कर और कर-छूट: 1764-1888 ई.); खास रूक्का परवाना बही (जोधपुर में लगाए गए वाणिज्यिक करों , छूटों, वार्षिक मेलों के अभिलेख: 1765-1831 ई.) ; कागादोन-री बहिस (व्यापारियों को विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर चेक-पोस्ट के माध्यम से सुगम पारगमन के लिए भेजे गए दस्तावेज़ , करों का रिकॉर्ड , हुंडी, लेन-देन के नकद मूल्य , विभिन्न

www.ignited.in

प्रांतों में उपयोग किए जाने वाले सिक्के आदि: 1754 - 1801); कामथाना बहिस (कुशल और अकुशल श्रमिकों और कारीगरों को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण: 1751-1768 ई.); ज़कात बहिस (दस्तावेज़ वाणिज्यिक उत्पादों का व्यापार, व्यापार मार्ग, परिवहन के साधन, व्यापारी का नाम और जाति, पारगमन कर की राशि (ज़कात) राजस्व एकत्र किया गया, आदि, 1799-1833); बयावरी-बाहिस (गाँव में विवाह से संबंधित सभी लेन-देन के दस्तावेज़ों में आयातित सामान, भोजन, कपड़े, आभूषण और कलाकृतियों पर व्यय शामिल हैं: 1719-1752) ; सावा बही मंडी सदर (मंडी का दस्तावेजीकरण या जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और राजस्थान के बाहर के प्रांतों के बीच मुख्य बाजार लेनदेन , जिसमें विभिन्न कस्बे आदि पर लगाए गए करों का विवरण शामिल है); अर्हसत्ता (टोज़ी, या खुले कागज जिसमें व्यापार कर, व्यापार की गई वस्तु, व्यापारी का नाम और जाति का विवरण हो) ; चिट्ठी (जयपुर के दीवान द्वारा परगना के अधिकारियों को लिखे गए पत्र जिसमें जागीरदारी और जमींदारी प्रणाली के कामकाज , वाणिज्यिक प्रथाओं , मध्यस्थता के तरीकों , व्यापारियों और व्यापारियों को रियायतें आदि के विवरण के साथ) ; और जयपुर के कारखानजात दस्तावेज (निर्माण इकाइयों से संबंधित) जैसे खशबू खाना (इत्र), रंग खाना (कपड़े की रंगाई), सूरत खाना (नक्शे, रेखाचित्र, पेंटिंग, लैंडस्केप आदि), शीर्ष खाना और सिलेह खाना (उत्पादन और हथियारों और विस्फोटक कवच आदि की मरम्मत, पालकी खाना (यात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली पालकी बनाना और मरम्मत करना) आदि।

अर्थव्यवस्था और व्यापार के विभिन्न पहलुओं की वर्तमान समझ को समृद्ध करने के लिए , ग्रामीण समुदायों, कारीगरों और उनके वेतन , व्यापारियों, व्यापारियों और कारीगरों की सामाजिक संरचना के बारे में व्यापक जानकारी का पता लगाने के लिए इन प्राथमिक स्रोतों की सावधानीपूर्वक जांच की गई। , व्यापारिक समुदाय , निर्माण तकनीक और प्रौद्योगिकियां, व्यापार मार्ग और उनकी सुरक्षा , परिवहन टोल, वसूली और मुआवजे की व्यवस्था आदि के बारे में नीतियां। इन दस्तावेजों की पहचान निम्नलिखित में से एक के रूप में की गई थी:

- खसरा, रकबा-बंदी, तकसीम, तरीज, हल की याददाश्त जैसे विभिन्न ग्राम-स्तरीय विवरण , क्षेत्र, व्यक्तियों पर कर आदि देने वाले दस्तावेज।
- ग्रामीण और परगना स्तर पर आय, व्यय और शेष के करों के खातों जैसे अर्हसत्ता , जमा-बंदी, जमा खर्च, मुवज़ाना, आदि का दस्तावेज।
- मूल्य सूची, निर्ख बाजार, निर्ख-रोजनामा
- अधिकारियों द्वारा जारी पत्रों और दस्तावेजों का संग्रह जैसे कि चिट्ठी , परवाना, सनद, अर्ज़दश्त आदि।
- प्रशासनिक मैनुअल जैसे दस्तूर , दस्तूर-उल अमल, अमल दस्तूर आदि, और
- अंबर/जयपुर कोर्ट का पत्राचार जैसे वकील रिपोर्ट, खुटुट-ए-महाराजगन (दिनांकित और अदिनांकित दोनों)।

इनमें से अधिकांश दस्तावेज राजस्थानी लिपि में हैं , जो ज्यादातर संवत युग में दिनांकित हैं , जो हिंदू कैलेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। एक समान तुलना की अनुमति देने के लिए, हिंदू कैलेंडर में तिथियों को 57 वर्ष घटाकर अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले के कुछ दस्तावेज़ हिजरी युग (इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार अरबी युग की गणना) में दिनांकित हैं , जबकि कुछ अन्य फसली कैलेंडर (भारतीय फसल के मौसम के आधार पर) में दिनांकित हैं। इन दोनों के बीच , फसली कैलेंडर संवत कैलेंडर के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

राजस्थान का भूगोल और गाँव की रूपरेखा

राजपुताना क्षेत्र (अब राजस्थान) को अरावली पर्वतमाला द्वारा दो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो राज्य के माध्यम से दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक फैली हुई है (मानचित्र 1 देखें)। रेंज के उत्तर-पश्चिम में , 60 प्रतिशत क्षेत्र में रेतीला इलाका है , जो अनुत्पादक है और इसमें बहुत कम पानी है। इसका अधिकांश भाग ग्रेट इंडियन थार मरुस्थल से आच्छादित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मारवाड़ या राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण-पूर्व में , शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र है जो ऊंचाई में अधिक है , जिसमें उपजाऊ मिट्टी और मेवाड़ के पहाड़ी इलाके से लेकर कोटा और बूंदी में टेबललैंड तक विविध स्थलाकृति है , और भरतपुर के समतल मैदान हैं।

मेवाड़ क्षेत्र में कई वर्षा आधारित नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ बहती हैं जिसके परिणामस्वरूप उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की बेहतर संभावनाएँ हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश बस्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। दूसरी ओर , मारवाड़ क्षेत्र में , अपर्याप्त मानसून के साथ , अनुपजाऊ भूमि थी जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता बहुत कम थी। किसी भी हिमाच्छादित नदी के अभाव में और वर्षा की अनियमित प्रकृति के कारण , इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए एकमात्र व्यवहार्य वैकल्पिक विकल्प सिंचाई के कृत्रिम तरीकों के माध्यम से भूमिगत जल का दोहन करना था।

18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान के गांवों में कृषि और पशुधन/डायरी मुख्य व्यवसाय थे। कृषि के विस्तार (और इसलिए राज्य के राजस्व को स्थिर करने) के लिए कृत्रिम सिंचाई के साधनों की आवश्यकता को सौंपा गया महत्व उनके निर्माण के लिए राज्य द्वारा नियमित रूप से दिए गए ऋणों की संख्या से स्पष्ट है। इसने नए गाँवों के बसने, खेती के विस्तार और दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दोहरी फसल को सक्षम किया, जिसके परिणामस्वरूप रबी और खरीफ मौसम की 55 फ़सलें हुईं जिनमें बाजरा , ज्वार, मोठ, मक्का, दालें शामिल थीं। , गेहूं, जौ और अनाज , नील, गन्ना, सिंघाड़ा जैसी नकदी फसलें , सब्जियां, तंबाकू और कपास, और व्यावसायिक फसलें जैसे तिलहन , कपास और अफीम।

जोधपुर के मेड़ता और जालौर9 जैसे परगनाओं में पशुपालन गतिविधियाँ जैसे भेड़ पालन और ऊन का निर्माण महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थीं। जालोर में ऊंटों का प्रजनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। वास्तव में, पूरा मारवाड़ क्षेत्र ऊंटों की अपनी नस्लों के लिए प्रसिद्ध था , जिनमें जूता , मल्लानी और फलौदी शामिल थे। मल्लानी और सांचोर की दुधारू गायें और नागौर के बैल भी सभी प्रमुख क्षेत्रीय और स्थानीय मेलों में अपने दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे। भेड़ की ऊन , दूध और दुग्ध उत्पादों , ऊन और चमड़े से बने फैंसी कंबल , पगड़ी और स्कार्फ का उत्पादन और व्यापार किया जाता था (टॉड, 1832)। लगाए गए करों की संख्या और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त होने वाले राजस्व के आधार पर चरवाही गतिविधियों के बढ़ते महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। कालांतर में , राजस्थान के कुछ हिस्सों में , देहाती अर्थव्यवस्था ने इतना महत्व ग्रहण कर लिया कि यह अब खेती के लिए सहायक और पूरक व्यवसाय नहीं रह गया था।

राजस्थान कई गैर-कृषि और खनिज संसाधनों से समृद्ध था और इसलिए खनन एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) नमक: नमक और नमक का काम एक महत्वपूर्ण उद्योग था। बंजारे नमक का परिवहन करते थे जबकि बनिया अपना व्यापार करते थे [12]; (ii) मकराना की संगमरमर की खदानें जो अपनी मस्जिदों और मकबरों के निर्माण के लिए दिल्ली और आगरा को संगमरमर का निर्यात करती थीं; (iii) बैराठ (जयपुर), चैनपुर (मासवास) और बीदासर[13] में तांबे का खनन ; (iv) लोहे का मुख्य रूप से मालपुर, नागौर और भीमल में खनन होता है; (v) सोजल, जैतारण और जौस जैसे परगना में पाए जाने वाले चांदी, सीसा और टिन; (vi) अजमेर के निकट तारागढ़ की पहाड़ियों में सीसे का खनन आगरा [14] को निर्यात किया गया; (vii) नागौर के पास पाए जाने वाले जिप्सम को पलस्तर के लिए सीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है[15] (टॉड, 1832) आदि।

मानचित्र 1. राजस्थान का मानचित्र

गैर-कृषि उत्पादन क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है , जिसमें कृषि-आधारित उत्पादों का उत्पादन और बुनकरों , रंगरेजों, दर्जियों, कुम्हारों, लुहारों, सुनारों, तेलियों, निर्माण श्रमिकों सहित कारीगरों का बढ़ता वर्ग शामिल है। कुछ गाँवों में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र का सापेक्षिक हिस्सा और महत्व कृषि क्षेत्र से अधिक था। पारंपरिक ग्रामीण शिल्प (जमदारी) के उत्पादन से एकत्र कर अक्सर कृषि (बिघोरी) से होने वाली प्राप्तियों से अधिक होता है। इसलिए राज्य ने कारीगरों और उनके शिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। शिल्प उत्पादन धीरे-धीरे शहरी केंद्रों में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था , हालांकि एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवसाय के रूप में।

www.ignited.in

शहरी केंद्रों में कारीगरों द्वारा उत्पादन मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए था क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान बढ़ते मुद्रीकरण के मद्देनजर उनके उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई थी (हबीब, 1963; पियर्सन और नकवी, 1974; भदानी, 1999; बेली, 1988)।

राजस्थान की स्थिति ने राज्य को रणनीतिक लाभ प्रदान किया क्योंकि यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता था। यह मालवा, गुजरात, मुल्तान और सिंध जैसे तटीय मुगल प्रांतों के साथ-साथ आगरा और दिल्ली की शाही राजधानियों के प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित है। इससे राज्य को अपनी सीमा से परे अपने व्यापार नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिली।

राजस्थान में संरचनात्मक परिवर्तन

- **बदलती कृषि अर्थव्यवस्था: किसानों का बोझ**

गाँव, जिसे मुख्य रूप से राजस्थान में एक कृषि बस्ती के रूप में माना जाता है, राज्य के लिए राजस्व पैदा करने की बुनियादी इकाई था। किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर खेती करते थे, जब तक कि राज्य के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए राज्य ने अलग-अलग गांवों में उनके प्रवास को मंजूरी नहीं दी। जागीरदारों को किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर राजस्व का आकलन (i) कृषि क्षेत्र में खेती योग्य भूमि की सीमा और (ii) देहाती क्षेत्र में मवेशियों (संख्या में) के आधार पर किया गया था। फसल बँटवारा कृषि में काश्तकारी का प्रमुख रूप था और बहुत बार किसान को अपनी फसल का हिस्सा नकद में जमा करना पड़ता था (रायचौधरी और अन्य , 1883)। हालाँकि, जयपुर के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से राज्य को फसल-हिस्सा भुगतान के उदाहरणों को इंगित करते हैं , जिन्हें बाद में राज्य द्वारा अनाज डीलरों को बेच दिया गया था , जिसका कुल मूल्य अर्हसत्ता में दर्ज किया गया था।

राजस्थान के कई क्षेत्र स्वाभाविक रूप से नाजुक और आपदा प्रवण थे , जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता बहुत कम थी। उदाहरण के लिए , बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में, कम कृषि उत्पादकता का मतलब है कि हैसिल (राजस्व प्राप्ति) से औसत आय इसकी कुल आय का 40% से कम थी। अल्प संसाधनों वाले अधिकांश किसान निर्वाह और व्यापक खेती में लगे हुए हैं। मराठों और पिंडारी सेना के असामान्य रूप से उच्च आंदोलन के कारण भारी राज्य की मांग और उनकी फसलों और मवेशियों के लिए खतरे ने उन्हें राज्य और स्थानीय साहूकारों से लगातार समर्थन लेने के लिए मजबूर किया। दोहरी फसल के लिए उपयुक्त भूमि के केवल एक छोटे से हिस्से के साथ , सघन खेती की गुंजाइश सीमित रही।

राज्य की राजनीतिक विचारधारा मुख्य रूप से गांवों से आय के एक स्थिर प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता से आकार लेती थी। 18वीं सदी के पूर्वार्द्ध में कीमतों में राजस्व मांग की तुलना में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसने नकदी फसलों की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि को प्रेरित किया , जिसने उच्च मूल्य प्राप्त किया और उच्च राज्य करों को भी आकर्षित किया (सिंह, 1974; गुप्ता, 1986; बाजेकल, 1988)। मुगलों से वित्तीय सहायता के अभाव में , राज्य कृषि उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ अन्य गैर-कृषि करों (देवरा , 1978; देवरा, 1981) के दोहन के लिए उत्सुक था। इस बात का अहसास बढ़ रहा था कि किसानों को ऋण और राज्य संरक्षण के निरंतर प्रावधान के बिना कृषि उत्पादन में आवश्यक विस्तार लाने के लिए राज्य अब किसान अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं कर सकता।

- **कृषि में गैर-किसान क्षेत्र का उदय**

राज्य ने कृषक कृषि को समर्थन देने और आय के अधिक अवसरों का दोहन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से गांव में व्यापारियों और साहूकारों द्वारा संचित पूंजी संसाधनों को कृषि में वापस लाने के उद्देश्य से क्रेडिट नेटवर्क का विस्तार करने के सभी प्रयास किए। इन संसाधन संपन्न व्यक्तियों में गैर-किसान मध्यम और उच्च वर्ग जाति के व्यक्ति, छोटे और बड़े व्यापारी और साहूकार और राज्य के साथ-साथ ग्रामीण स्तर के अधिकारी शामिल थे , जो संयुक्त रूप से सेठिया (2003) को 'गैर-किसान क्षेत्र' कहते हैं। इसके बाद कृषि उत्पादन के आयोजन और प्रबंधन के विभिन्न नए रूपों का उदय हुआ। बड़े और शक्तिशाली व्यापारी, जिन्होंने शुरुआत में केवल राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य को पैसा उधार दिया, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान राजस्व खेती में भागीदारी के माध्यम से कृषि उत्पादन में प्रवेश किया। राज्य ने कृषि को 'सरकारी हल' के रूप में भी संगठित किया और इस प्रकार खेती करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए

सही समय पर राज्य हलों से उत्पादित उत्पादों को बाजार में बेचा गया।

कृषि में गैर-किसानों और राज्य की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन का विस्तार हुआ। अनाज के विशाल भंडार के साथ , गैर-किसानों ने अपने अधिशेष को बेचने के लिए अधिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी , ऐसे समय में जब उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलेगी (कमी के वर्षों के दौरान)। जैसे ही राज्य ने गैर-किसानों को तालुका या जागीर के रूप में भूमि सौंपी , नए गाँव सामने आए। कृषि को बाजारों से जोड़ने के परिणामस्वरूप लाभदायक वाणिज्यिक उत्पादन हुआ और इससे गैर-किसान कृषि के विस्तार में और मदद मिली।

- **एक समग्र और शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग का उदय**

राज्य ने उभरते हुए व्यापारी वर्ग का संरक्षण किया , जिसमें धन उधार देने , धन के विनिमय और हस्तांतरण और व्यापार में लगे व्यक्ति शामिल थे। व्यापारियों के पास संचित पूंजी को कृषि में लगाने से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और इस तरह के विकास के स्पिन-ऑफ के रूप में नए बाजार और शहर विकसित हुए। राजस्व संग्रह और व्यापार के बीच एक गठजोड़ बनाया गया था।

व्यापारी समुदाय में न केवल पारंपरिक 'वैश्य' उपजातियाँ शामिल थीं, बल्कि अग्रवाल, ओसवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल, पोरवाल, पालीवाल, श्रीमल और खत्री भी शामिल थे। इसमें ब्राह्मण, गोसाईं, चारण और भाट भी शामिल थे। बलदिया और बंजारे खुदरा विक्रेता थे जो माल की ढुलाई भी करते थे और व्यापार नेटवर्क16 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

17वीं शताब्दी के अंत तक , रियासतें पहले से ही राजचिह्न और प्रशासनिक तंत्र के रखरखाव से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए व्यापारियों पर निर्भर थीं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में , सेना पर खर्च में वृद्धि और मराठों की बढ़ती मांगों ने व्यापारियों और साहूकारों पर शासकों की निर्भरता को और बढ़ा दिया। नतीजतन, जबकि राज्य की उधारी स्थायी ऋणग्रस्तता में बदल गई, व्यापारियों ने राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में काफी महत्व ग्रहण कर लिया। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्व खेती में व्यापारी वर्ग की भागीदारी को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक , यह व्यापारियों को राज्य ऋण की अदायगी का एक स्वीकार्य रूप बन गया। इसने व्यापारियों को कृषि अधिशेष तक सीधी पहुंच प्रदान की जिसे वे अनाज बाजारों में बेच देते थे।

बाजारों और बाजार-कस्बों के विस्तार के साथ फलता-फूलता व्यापार

18वीं सदी के मध्य में राजस्थान में व्यापारियों और व्यापारियों के शक्तिशाली समूह के नियंत्रण में बनिया-राज्य का उदय हुआ (भार्गव , 1935)। अनाज के उत्पादन और विपणन में व्यापारियों की अधिक भागीदारी के साथ अनाज व्यापार पर राज्य का नियंत्रण कमजोर हो गया। हालाँकि , इसने व्यापक व्यावसायीकरण और बाजारों को चौड़ा करने का नेतृत्व किया क्योंकि किसानों , कारीगरों, व्यापारियों और व्यापारियों के साथ-साथ आस-पास की रियासतों ने व्यापार नेटवर्क में भाग लिया। राज्य ने व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और समर्थन किया। इसने नए कस्बा (बाजार-कस्बे या शहर) विकसित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए, जो पड़ोसी गांवों के बीच वस्तुओं के आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में काम करेंगे। मारवाड़ क्षेत्र में भीनमाल , जालौर, मंडोर, नागौर और पाली जैसे कई शहर राजस्थान और उत्तरी भारत (गुप्ता , 1986) दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हुए।

इन कस्बों में बसने के लिए अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ व्यापारियों और बंजारों को दुकानें और गोदाम (भंडारण सुविधाएं) प्रदान किए गए थे। उन्हें स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों या आक्रमणकारियों द्वारा जबरन वसूली या जबरन वसूली के किसी भी कार्य से सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। व्यापारियों और व्यापारियों को विभिन्न पारगमन और बिक्री करों जैसे कि सैर-बांध , माप-बांध और रहदारी से छूट दी गई थी, और उन्हें अपने घर और दुकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी गई थी (शर्मा , 1980)। नए कस्बों में व्यापार लेनदेन18 पर करों की एक अधिक उदार प्रणाली ने न केवल बड़े व्यापारियों के लिए , बल्कि छोटे व्यापारियों और बंजारों के लिए भी काफी लाभ मार्जिन सुनिश्चित किया, बाद वाले को भी एक विस्तारित व्यापार नेटवर्क के करीब बांध दिया।

निष्कर्ष

18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान ने मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ-साथ मराठों द्वारा बार-बार किए गए हमलों को देखा , जिन्होंने राजपूतों से काफी

www.ignited.in

श्रद्धांजलि ली। इसने क्षेत्र को आर्थिक रूप से सूखा दिया और राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बनाया। राज्य ने साधन-संपन्न व्यापारी वर्ग को साथ लेकर कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए लक्षित प्रयास किए। व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित राज्य की नीतियों ने एक क्रॉस-कास्ट व्यापारी वर्ग के उद्भव की सुविधा प्रदान की। स्वदेशी विकास कृषि और स्थानीय बाजारों में व्यापारियों और व्यापारियों की भागीदारी से सुगम हुआ, जो व्यापक व्यापार नेटवर्क के साथ एकीकृत हो गया। इस प्रकार, इस अवधि में राजस्थान में अधिकांश रियासतों में कृषि विस्तार के साथ-साथ व्यापार नेटवर्क का विस्तार देखा गया। सूचना के विश्लेषण और अभिलेखीय अभिलेखों के आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष 18वीं शताब्दी की 'अंधकार युग' की धारणा को काफी हद तक बदल देते हैं।

ग्रन्थसूची

1. बाजेकल, एम. (1988). अठारहवीं सदी के पूर्वी राजस्थान में राज्य और ग्रामीण अनाज बाजार। द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू , 25(4), 443-473।

2. बेली, सीए (1988)। शासक , शहरवासी और बाज़ार: ब्रिटिश विस्तार के युग में उत्तर भारतीय समाज , 1770-1870 (संख्या 28)। कप आर्काइव।

3. भदानी, बी.एल. (1992). सत्रहवीं सदी के पश्चिमी राजस्थान में कृषि उपज में भूमि कर और व्यापार। द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू , 29(2), 215-225।

4. भदानी, बी.एल. (1999). किसान कारीगर और उद्यमी। जयपुर।

5. भार्गव, बी. (1935). प्राचीन और मध्यकालीन भारत में स्वदेशी बैंकिंग। डीबी तारापोरवाला संस एंड कंपनी।

6. देवरा, जी.एस.एल. (1981)। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। धरती प्रकाशन, बीकानेर।

7. देवरा, जी.एस.एल. (1978). राजस्थान और सिंध/मुल्तान के बीच व्यापार-संबंधों का अध्ययन (1650-1800 ई.)। भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाही में (वॉल्यूम 39 , पीपी. 581-594)। भारतीय इतिहास कांग्रेस।

8. गुप्ता, एस.पी. (1986). पूर्वी राजस्थान की कृषि प्रणाली, सी। 1650-सी। 1750. मनोहर।

9. हबीब, आई. (1963). मुगल भारत की कृषि प्रणाली , 1556-1707 (पृष्ठ 1)। बॉम्बे: एशिया पब्लिशिंग हाउस।

10. पियर्सन, एमएन, और नकवी, एचके (1974)। ऊपरी भारत में शहरी केंद्र और उद्योग 1556-1803। अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी का जर्नल। 94(2): 264 (1974)

11. रायचौधरी, टी., कुमार, डी., हबीब, आई., और देसाई, एम. (एड्स.)। (1983)। द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया: वॉल्यूम 2 , सी. 1757-सी। 1970 (नंबर 2)। कप आर्काइव।

12. सेठिया, एम.टी. (2003). राजपूत राजनीति , योद्धा, किसान और व्यापारी, 1700-1800। रावत बुक्स.

13. शर्मा, जी. डी. (1980)। अठारहवीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी राजस्थान में व्यापारी और महाजन। भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाही में (वॉल्यूम. 41, पीपी. 377-385). भारतीय इतिहास कांग्रेस।

14. सिंह, डी. (1974). 18वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महाजनों की भूमिका। सामाजिक वैज्ञानिक, 20-31।

15. टॉड, जे। (1832)। राजस्थान या भारत के मध्य और पश्चिमी राजपूत राज्यों के इतिहास और पुरावशेष, (खंड 2)। लंदन: स्मिथ, एल्डर।

Corresponding Author

सुख लाल यादव*

पीएच.डी शोधकर्ता , सनराईस विश्वविद्यालय , अलवर, राजस्थान